RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 245
दि. 05.01.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया

भारत के विकास की कहानी और वॉलीबॉल के खेल में कई समानताएं हैं; वॉलीबॉल हमें सिखाता है कि कोई भी जीत अकेले प्राप्त नहीं की जा सकती और हमारी सफलता हमारे समन्वय, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तैयारी पर निर्भर करती है: प्रधानमंत्री

हर किसी की अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी होती है और हम तभी सफल होते हैं जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाता है; हमारा राष्ट्र भी ठीक इसी तरह प्रगति कर रहा है: प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें वाराणसी से सांसद होने के नाते सभी खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप आज से वाराणसी में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ी अथक परिश्रम के बाद इस राष्ट्रीय टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं और आने वाले दिनों में वाराणसी के मैदान पर उनके परिश्रम की परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि देश के 28 राज्यों की टीमें एकत्रित हुई हैं जो एक भारत, श्रेष्ठ भारत का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती हैं। प्रधानमंत्री ने चैंपियनशिप के सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी।

बनारसी की एक स्थानीय कहावत का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ी अब वाराणसी पहुंच चुके हैं और शहर को अच्छी तरह जान लेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वाराणसी खेल प्रेमियों का शहर है जहां कुश्ती, कुश्ती के अखाड़े, मुक्केबाजी, नौका दौड़ और कबड्डी बहुत लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी ने कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यूपी कॉलेज और काशी विद्यापीठ जैसे संस्थानों के खिलाड़ियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। श्री मोदी ने कहा कि हजारों वर्षों से वाराणसी ज्ञान और कला की खोज में आने वाले सभी लोगों का स्वागत करता आया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दौरान वाराणसी का उत्साह बरकरार रहेगा, खिलाड़ियों को उनका उत्साहवर्धन करने के लिए दर्शक मिलेंगे और वे वाराणसी की समृद्ध आतिथ्य

सत्कार की परंपरा का अनुभव भी करेंगे।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वॉलीबॉल कोई साधारण खेल नहीं है बल्कि यह संतुलन और सहयोग का खेल है जहां गेंद को हमेशा हवा में मंत्र से प्रेरित होता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भले ही प्रत्येक खिलाड़ी के पास अलग-अलग कौशल हों लेकिन सभी अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। श्री मोदी ने भारत के विकास की कहानी और वॉलीबॉल के बीच समानताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह खेल सिखाता है कि कोई भी जीत अकेले प्राप्त नहीं होती बल्कि जीत समन्वय, विश्वास और टीम की तैयारी पर निर्भर करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर किसी की अपनी भूमिका और जिम्मेदारी होती है और सफलता तभी मिलती है जब हर कोई गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भी इसी तरह प्रगति कर रहा है, स्वच्छता से लेकर डिजिटल भुगतान तक, 'एक पेड़ मां के नाम' से लेकर विकसित भारत के अभियान तक, हर नागरिक, हर वर्ग और हर प्रांत सामूहिक चेतना और 'भारत पहले' की भावना के साथ काम कर रहा है।

श्री मोदी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की विकास और अर्थव्यवस्था की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रगति केवल आर्थिक मोर्चे तक ही सीमित नहीं है बल्कि खेल जगत में दिख रहे आत्मविश्वास में भी झलकती है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में, 2014 से विभिन्न खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है और उन्हें जेन-जेड खिलाड़ियों को मैदान पर तिरंगा फहराते देखकर गर्व महसूस होता है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि एक समय ऐसा था जब सरकार और समाज दोनों ही खेलों के प्रति उदासीन थे जिससे खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रहती थी और बहुत कम युवा खेलों को अपना करियर बनाते थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले एक दशक में खेलों के प्रति सरकार और समाज दोनों की सोच में बदलाव आया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने खेल के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है और आज भारत का खेल मॉडल 'खिलाड़ी-केंद्रित' हो गया है जिसमें प्रतिभा की पहचान, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, पोषण और पारदर्शी चयन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि खिलाड़ियों के हितों को हर स्तर पर प्राथमिकता दी जाए।

प्रधानमंत्री ने कहा, ह्लआज देश में तेजी से सुधार हो रहे हैं, हर क्षेत्र और हर विकास लक्ष्य इससे जुड़ा हुआ है, और खेल भी उनमें से एक है।ह्व उन्होंने बताया कि सरकार ने खेल के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं जिनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम और खेलो भारत नीति 2025 शामिल हैं। इनसे प्रतिभाओं को अवसर मिलेंगे और खेल संगठनों में पारदर्शिता बढ़ेगी।

यूपी में व्यापार और निवेश का बन रहा बेहतर माहौल, सीएम योगी से मिले सीआईआई के प्रतिनिधि

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश अब बेहतर कानून व्यवस्था और स्थिर प्रशासनिक माहौल के चलते देशभर के उद्योग जगत की पहली पसंद बनता जा रहा है. सुरक्षा, अनुशासन और निष्पक्ष शासन ने निवेशकों का भरोसा प्रदेश में मजबूत किया है. इसके परिणामस्वरूप बड़े, मध्यम और छोटे तीनों सेगमेंट के उद्योग तेजी से उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष राजीव मेमानी, नई दिल्ली, उमाशंकर भरतिया, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, इण्डिया ग्लाइको लि०, दिल्ली / नोएडा और सुनील मिश्रा ने मुलाकात कर निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विस्तार को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया.

'पहले की तुलना में काम करना हुआ आसान'

प्रतिनिधियों ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश का सिस्टम और गवर्नेंस मॉडल पूरी तरह बदला है. अब जमीन पर काम करना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हुआ है और परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही हैं.

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ाने पर विचार-विमर्श

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के विजन में उद्यमी सहयोग करना चाह रहे हैं. सीएम योगी के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए भी विचार विमर्श किया गया.

शीतलहर के चलते चंडीगढ़ के स्कूलों में बढ़ाई गई छुट्टियां?

चंडीगढ़ में जनवरी की शुरूआत से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फीली हवाओं की वजह से शहर में

शीतलहर का कहर है। मौसम को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सर्दी की छुट्टियों में बदलाव किया है। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा 4 जनवरी 2026 को जारी आदेश के अनुसार, शहर के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों की फिजिकल कक्षाएं 10 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगी। प्ले ग्रुप के बच्चों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।

शिवराज सिंह चौहान ने आईसीएआर द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 नई किस्में राष्ट्र को किया समर्पित

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा 33.26 करोड़ रु. के लाभांश का चेक केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को भेंट

वर्ष 1969 से अब तक 7205 फसल किस्मों को मंजूरी, वहीं मोदी सरकार के 11 साल में 3236 नई उच्च उत्पादक किस्में- कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

किसानों की आय बढ़ाने में बड़ी छलांग, भारत बनेगा विश्व का 'फूड बास्केट'- श्री शिवराज सिंह चौहान

आईसीएआर और कृषि विश्वविद्यालयों के शोध से बीज क्रांति, विशेष गुणों वाली उच्च उत्पादक किस्में

सूखा-लवणीयता जैसी चुनौतियों से निपटने में कारगर- श्री शिवराज सिंह चौहान

देश ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर 150.18 मिलियन टन उत्पादन के साथ नया कीर्तिमान स्थापित किया- केंद्रीय कृषि मंत्री

(जीएनएस)।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के एनएएससी कॉम्प्लेक्स स्थित ए.पी. शिंदे ऑडिटोरियम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 25 फील्ड फसलों की 184 उन्नत किस्मों का अनावरण किया। यह कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तत्वावधान में आयोजित किया गया जिसमें वैज्ञानिकों, वरिष्ठ अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों ने सहभागिता की।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने उच्च उत्पादक बीजों के विकास में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। वर्ष 1969 में शुरू हुई गजट अधिसूचना प्रक्रिया के बाद अब तक कुल 7205 फसल प्रजातियों को अधिसूचित किया जा चुका है जिनमें धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, दलहन, तिलहन, रेशेदार और अन्य फसलें शामिल हैं, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11-12 वर्षों में नई किस्मों के विकास की गति और तेज हुई है, अकेले इस अवधि में 3236 उच्च उत्पादक प्रजातियों को मंजूरी मिली है, जबकि 1969 से 2014 तक 3969 प्रजातियों को अधिसूचित किया गया था। अब अधिसूचित 184 उन्नत किस्मों का लोकार्पण किया गया है, जो देश के किसानों को अधिक उपज, बेहतर गुणवत्ता और जलवायु सहनशीलता जैसे लाभ देंगी।

उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की फसल संबंधी समन्वित परियोजनाओं के तहत परिषद की संस्थाओं, राज्य व केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और निजी बीज कंपनियों ने मिलकर इन किस्मों के विकास में अहम योगदान दिया है। विशेष गुणों वाली कई प्रजातियां, जैसे सूखा सहनशील, लवणीय-क्षारीय मिट्टी में उपज देने वाली और रोग-कीट प्रतिरोधी किस्में, किसानों को बदलते मौसम और जलवायु संकट से सुरक्षा कवच देंगी।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत उच्च उत्पादक और जलवायु सहनशील बीजों के विकास के दम पर कृषि में नई क्रांति के दौर में प्रवेश कर चुका है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की फसलों की अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं, राज्य व केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और निजी बीज कंपनियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। कुल 184 हाल की प्रजातियों के विकास में परिषद की संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों ने क्रमशः 60, 62 और 62 प्रजातियों के साथ योगदान दिया है।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कई नई लोकार्पित किस्मों में सूखा, बाढ़, लवणीयता और रोग-कीट प्रतिरोध जैसे विशेष गुण निहित हैं, जो मौसम की अनिश्चितता के बीच स्थिर उत्पादन सुनिश्चित करेंगे। उच्च पैदावार के साथ-साथ इन किस्मों में बेहतर गुणवत्ता, पोषण-समृद्धि और प्रसंस्करण-उपयुक्तता जैसे गुण भी हैं, जिससे किसानों को बाजार में बेहतर दाम और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न मिलेगा। यह 'लैब से लैंड' की यात्रा का सफल मॉडल है।

उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि हर किसान के खेत तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुंचें, ताकि भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अन्न उत्पादन करने वाला देश बने।

एडीए का दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 'एयरोनॉटिक्स 2047' बेंगलुरु में शुरू हुआ

(जीएनएस)।

एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 'एयरोनॉटिक्स 2047' का शुभारंभ 4 जनवरी, 2026 को बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स (सीएबीएस) में हुआ। संगोष्ठी का उद्घाटन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने किया। अपने संबोधन में वायुसेना प्रमुख ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस के 25 वर्ष पूरे होने पर एडीए को बधाई दी और आज के निरंतर बदलते समय में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को परिचालन रूप से तैयार रखने के लिए सुपुर्दगी की समयसीमा का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस अवसर पर बोलते हुए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास के महत्व पर जोर दिया जिससे 2047 तक विकसित भारत के परिकल्पना को साकार किया जा सके।

इस संगोष्ठी में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, औद्योगिक भागीदार, शिक्षाविद, विमानन क्षेत्र के अग्रणी और एयरोस्पेस क्षेत्र के वक्ता एक साथ आए हैं ताकि वे वैमानिकी के विकास, डिजाइन नवाचार, विनिर्माण और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार साझा कर सके। एयरोनॉटिक्स-2047 का मुख्य उद्देश्य आधुनिक एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं का पता लगाना है, जिनमें अगली पीढ़ी के विमानों के लिए विनिर्माण और असेंबली, डिजिटल विनिर्माण, अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए वायुगतिकी, प्रणोदन प्रौद्योगिकियां, उड़ान परीक्षण तकनीकें, डिजिटल ट्विन प्रौद्योगिकी, प्रमाणन चुनौतियां, उड़ान नियंत्रण प्रणाली और एवियोनिक्स, लड़ाकू विमानों में रखरखाव संबंधी चुनौतियां, विमान डिजाइन में एआई और एक्यूएटर्स के लिए सटीक विनिर्माण शामिल हैं।

इस संगोष्ठी में भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के भविष्य और एलसीए तेजस के प्रारंभिक डिजाइन से लेकर स्क्वाड्रन में शामिल होने तक के सफर पर चर्चा की जाएगी। एडीए ने एलसीए तेजस को डिजाइन और विकसित किया है। इसके 5,600 से अधिक सफल उड़ान परीक्षण हो चुके हैं। इस कार्यक्रम में सरकारी प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों सहित 100 से अधिक डिजाइन कार्य केंद्र शामिल थे।

श्री अमित शाह ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, जिला कलेक्टर तथा महानगर पालिका आयुक्त के साथ चर्चा कर आवश्यक सुझाव दिए

गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा गांधीनगर में जलजन्य टायफाइड की स्थिति को लेकर प्रशासन को युद्धस्तर पर कार्यवाही के आदेश

श्री अमित शाह ने मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा त्वरित और सटीक उपचार सुनिश्चित करने तथा अस्पताल में परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के आदेश दिए

श्री अमित शाह ने लीकेज की तत्काल मरम्मत करने और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के फैलाव को रोकने के लिए आसपास के क्षेत्रों में पाइपलाइन की सघन जांच के आदेश दिए

गांधीनगर, 04 जनवरी : गांधीनगर शहर के सेक्टर 24, 28 तथा आदिवाडा क्षेत्र में पानी की पाइप लाइन में लीकेज होने के कारण दूषित पानी से बच्चों एवं नागरिकों में टायफाइड के मामले सामने आए हैं। इस संदर्भ में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, जिला कलेक्टर तथा महानगर पालिका आयुक्त के साथ निरंतर संपर्क में रहकर चर्चा की, वर्तमान स्थिति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की तथा मौजूदा परिस्थिति से निपटने के लिए युद्धस्तर पर कार्यवाही करने के सुझाव दिए हैं।

श्री अमित शाह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर टायफाइड से प्रभावित बच्चों एवं नागरिकों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा त्वरित और सटीक उपचार सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं, साथ ही गांधीनगर सिविल अस्पताल में पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों के लिए भोजन की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। श्री शाह ने लीकेज की तत्काल मरम्मत करने और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का और फैलाव न हो, इसके लिए आसपास के क्षेत्रों में भी पाइप लाइन की सघन जांच करने के आदेश दिए हैं।

गांधीनगर शहर में संदिग्ध टायफाइड मामलों को लेकर सघन स्वास्थ्य व्यवस्था एवं सर्वेक्षण कार्यवाही शुरू की गई है।

जिन क्षेत्रों से ये संदिग्ध मामले सामने आए हैं, उन सेक्टर 24, 26 और 28 तथा आदिवाडा क्षेत्रों में 75 हेल्थ टीमों द्वारा सर्वेक्षण किया गया है।

अब तक संदिग्ध टायफाइड के 113 मामले सामने आए हैं, जिनमें से उपचाराधीन मरीजों में से 19 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। शेष 94 मरीजों को गांधीनगर सिविल अस्पताल तथा सेक्टर 24 और 29 के यूएचसी में उपचार दिया जा रहा है तथा सभी मरीजों की स्थिति स्थिर है। प्रभावित क्षेत्रों में 247 ओपीडी शुरू की गई है। जिन मरीजों का उपचार सिविल अस्पताल में किया जा रहा है, उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है।

गांधीनगर महानगर पालिका की सर्वेक्षण टीमों द्वारा अब तक 20,800 से अधिक घरों का सर्वे कर 90 हजार से अधिक जनसंख्या को कवर किया गया है।

रोग रोकथाम के उपायों के अंतर्गत 30 हजार क्लोरीन टैबलेट और 20,600 ओआरएस पैकेट का वितरण किया गया है।

सम्पादकीय

अपनी कार्यकुशलता से छाप छोड़ते सीएम साय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को नईं दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि अब तक राज्य में विकास की गतिविधियां नक्सली हिसा के कारण बाधित थीं किन्तु इस वक्त राज्य में वाम उग्रावाद समाप्त प्रायः है। राज्य में सरकार तेजी से विकास कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जब दो वर्ष पूर्व राज्य में संपन्न हुए चुनाव में जनता ने उन्हें सरकार बनाने का अवसर दिया तो उस वक्त देश में नक्सल हिसा का 80 प्रातिशत अकेला छत्तीसगढ़ में था। किन्तु गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह वाम उग्रावाद समाप्त करने की घोषणा करके राज्य सरकार का नाम सिर्प उत्साह से बढ़ाया बल्कि छत्तीसगढ़ की तमाम विकास योजनाओं को लागू करने की प्रोरणा भी दी। दरअसल मुख्यमंत्री साय के कहने का तात्पर्य था कि यदि राजनीतिक प्राशासन ठान ले तो कठिन से कठिन समस्या का भी समाधान संभव है। छत्तीसगढ़ में इतने बीहड़ जंगल हैं कि इन्हीं में नक्सली खुद को अजेय समझते थे। मुख्यमंत्री साय के पहले की सरकार नक्सल समस्या को सामाजिक और आर्थिक बताकर नक्सलियों के प्राति कठोर रणनीति नहीं अपनाती थी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को कई चौंकाने वाली जानकारी दी। उनमें से एक है कि राशन लेने के लिए ग्रामीणों को पर्वत पार करके एक कस्बे तक जाना होता था। हैरानी की बात यह है कि ग्रामीण अपने गांव से पैदल ही कस्बे तक जाते थे तो उन्हें रात में पर्वत पर विश्राम करना होता था फिर राशन लेकर वापस होते वक्त दोबारा दूसरे दिन उसी पर्वत पर विश्राम करते थे, फिर तीसरे दिन वे अपने गांव में पहुंचते थे। मुख्यमंत्री साय ने ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उसी गांव में राशन की दुकान खुलवा दी। असल में मुख्यमंत्री साय यह कहना चाहते थे कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में वुछ ऐसे गांव हैं जिनका आज तक सव्रेक्षण ही नहीं हो पाया है। इसका एक ही कारण है कि भयंकर घने जंगलों में कब्जा करके नक्सली बैठे हुए थे। किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह उन गांवों में चला जाए। यही कारण है कि वे ग्रामीण सरकार की विकास योजनाओं से अछूते रह गए। वास्तविकता तो यह है कि सभी सरकारों ने जंगल के उन गावों में सड़क और बिजली की व्यवस्था के लिए स्कीम तो बनाया किन्तु उन्होंने नक्सली समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला इसलिए राज्य में विकास कार्यं अधूरा ही रह गया। बहरहाल मुख्यमंत्री ने विकास कार्यो की जानकारी दी जिसमें प्राधानमंत्री आवास के वुल 18 लाख घरों में से 8 लाख की चाबी उनके मालिक को देने की बात की। यही नहीं उन्होंने तो यहां तक कहा कि जो नक्सली हिसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं उन्हें न सिर्प प्रातिमाह 10 हजार रुपए की सरकारी अनुदान दिया जा रहा है बल्कि यदि वह शहर या देहात में आवास बनाना चाहते हैं तो राज्य सरकार निति नीतियों के अनुसार भूमि भी दे रही है। लब्बोलुआब यह है कि यदि कोई मुख्यमंत्री ठान ले तो पत्थर पर भी हरी-भरी घास उगा सकता है।

आयुष निर्यात संवर्द्धन परिषद ने नई दिल्ली में चौथी स्थापना वर्षगांठ मनाई

एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के उपायों और व्यापार समझौतों में शामिल होने के कारण 2024-25 में आयुष का निर्यात 6.11 प्रतिशत बढ़कर 68.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया

(जीएनएस)।

आयुष निर्यात संवर्द्धन परिषद (आयुषएक्सिल) ने आज नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों और वेलनेस उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों के तहत अपनी चौथी स्थापना वर्षगांठ मनाई।

अपनी स्थापना के बाद से, आयुषएक्सिल ने निर्यातकों की क्षमता निर्माण, निर्यात प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन को सुविधाजनक बनाने, और प्रमुख विदेशी बाजारों में बी2बी बैठकों, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, सेमिनारों और पहुंच कार्यक्रमों के आयोजन पर केन्द्रित कई पहल की हैं।

आयुष और हर्बल उत्पादों के निर्यात में 6.11 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 2023-24 में 64.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 68.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। आयुषएक्सिल की स्थापना के बाद, यह वृद्धि और तेज हुई है, जो भारत की पारंपरिक दवाओं और हर्बल उत्पादों के लिए बेहतर ग्लोबल पहुंच और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांग को दिखाता है।

भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों (आयुष) को द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में भी औपचारिक मान्यता मिली है, जिसमें भारत-ओमान सीईपीए और भारत-न्यूजीलैंड एफटीए शामिल हैं, जिनमें स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं और पारंपरिक चिकित्सा पर समर्पित एनेक्स हैं। आयुषएक्सिल को आयुष मंत्रालय के

आयुष क्वालिटी मार्क कार्यक्रम को संभालने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे डब्ल्यूएचओ शिखर सम्मेलन (17-19 दिसम्बर 2025) के दौरान शुरू किया था, जो आयुष प्रोडक्ट्स के क्वालिटी एश्योरेंस और वैश्विक मान्यता को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

जैसे ही आयुषएक्ससिल अपने पांचवें साल में प्रवेश कर रहा है, परिषद का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करना, मुक्त व्यापार समझौतों के तहत अवसरों का लाभ उठाना, गुणवत्ता और प्रमाणन ढांचे को बढ़ावा देना और भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की वैश्विक स्वीकृति को बढ़ाना है।

यह वर्षगांठ आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के विजन के अनुरूप, वैश्विक आयुष और वेलनेस अर्थव्यवस्था में भारत के बढ़ते नेतृत्व को रेखांकित करती है।

आयुषएक्सिल को 4 जनवरी 2022 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, नई दिल्ली में सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया गया था, और 20 अप्रैल 2022 को गुजरात के गांधीनगर में हुए ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने औपचारिक रूप से इसकी शुरूआत की थी। इसके बाद, 31 जुलाई 2023 को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने इस काउंसिल को आयुष सेक्टर के लिए नोडल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के तौर पर अधिसूचित किया।

यह परिषद आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर काम करती है, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, होम्योपैथी और अन्य भारतीय पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों से संबंधित उत्पादों और सेवाओं के निर्यात की देखरेख करती है।

राह-वीरः बिना किसी डर के जीवन बचाएं - नेक आदमी की सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है

(जीएनएस)।

सड़क दुर्घटना के दौरान हर पल महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर उस महत्वपूर्ण 'गोल्डन आवर' में जब समय पर सहायता मिलने से किसी की जान बच सकती है। ऐसे क्षणों में आगे आने वाले लोगों का समर्थन और सुरक्षा करने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 134ए के तहत 2020 में गुड समैरिटन रूल्स अधिसूचित किए। ये नियम एक सरल विश्वास पर आधारित हैं - दुर्घटना पीड़ित की सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने से कभी डरना नहीं चाहिए। जो लोग साहस दिखाते हुए किसी घायल अजनबी को उठाकर, अक्सर उसका नाम भी जाने बिना, उसे निकटतम अस्पताल ले जाते हैं, उन्हें राह-वीर कहा जाता है।

किसी दुर्घटना पीड़ित की सहायता करने वाले नेक आदमी को कानूनी झंझटों में नहीं फंसाया जा सकता, उससे व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता या उसे अनावश्यक रूप से हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। उनकी सहायता करने की इच्छा का सम्मान किया जाता है और उनकी गरिमा और

निजता की रक्षा की जाती है।

गोल्डन आवर में जीवन बचाना

कानून के अनुसार, गंभीर चोट लगने के बाद का पहला घंटा 'गोल्डन आवर' कहलाता है जो चिकित्सा सहायता के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस अवधि के दौरान त्वरित सहायता से आजीवन विकलांगता, आघात और अनगिनत मौतों को रोका जा सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राह-वीर बनने के लिए आपको चिकित्सा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। आपको विशेष उपकरणों की भी आवश्यकता नहीं है। कभी-कभी, आपकी सहायता करने की इच्छा ही सबसे बड़ी सहायता होती है।

एक नेक आदमी बननाः आपको जानना चाहिए - क्या करें और क्या न करें

क्या करेंः आपके अधिकार और जिम्मेदारियां

बिना किसी डर के सहायता करेंः सद्भावना से कार्य करने पर आपको कानूनी रूप से नागरिक या आपराधिक दायित्व से सुरक्षा प्राप्त है।

यह जान लें कि आप गुमनाम रह सकते हैंः जब तक आप गवाह बनना न चाहें, तब तक आपको व्यक्तिगत विवरण साझा करने की आवश्यकता नहीं है।

कृपया केवल एक बार ही पुलिस को बयान दे सकते हैंः यदि आप गवाह के रूप में स्वेच्छा से उपस्थित होते हैं तो आपकी सुविधानुसार किसी भी समय और स्थान पर आपसे एक बार पूछताछ की जा सकती है।

अस्पताल से रसीद अवश्य प्राप्त करेंः आपको इस बात की साधारण पुष्टि प्राप्त करने का अधिकार है कि आप पीड़ित को उपचार के लिए लाए थे।

क्या न करेंः वे मिथक जिन पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए

कानूनी चिंताओं के कारण संकोच न करेंः यह प्रणाली राह-वीरों की रक्षा के लिए बनाई गई है।

अस्पताल में रुकने के लिए बाध्य महसूस न करेंः एक बार मरीज को भर्ती कर लिया जाए तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

इलाज के लिए भुगतान न करेंः अस्पताल आपातकालीन देखभाल के लिए आपसे भुगतान की मांग नहीं कर सकते।

एफआईआर दर्ज कराने या गवाही देने के लिए खुद को बाध्य महसूस न करेंः गवाह बनना आपकी व्यक्तिगत पसंद है।

यदि आप गुमनाम रहना पसंद करते हैं तो व्यक्तिगत विवरण प्रकट न करेंः यह आपका अधिकार है।

अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने की अनुमति न देंः इसकी अनुमति नहीं है।

हमें और अधिक राह-वीरों की आवश्यकता है

बेहतर सड़कों और बढ़ते बुनियादी ढांचे के बावजूद, भारत में सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने और मरने वालों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। इसके अलावा, भारत दुनिया में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं वाले देशों में से एक है। वास्तव में, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि इन दुर्घटनाओं का आर्थिक प्रभाव बहुत बड़ा है जिससे देश को अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 3 प्रतिशत नुकसान होता है। यह आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट में बताया गया है।

सड़कें लोगों को जोड़ने और अवसर पैदा करने के लिए होती हैं, फिर भी अक्सर वे दुखद, रोकी जा सकने वाली दुर्घटनाओं का कारण बन जाती हैं। इनमें से कई मौतें इसलिए नहीं होती कि सहायता संभव नहीं थी बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि सहायता समय पर नहीं पहुंच पाती। राहगीर अक्सर पुलिस की पूछताछ, अस्पताल की प्रक्रियाओं या कानूनी पेचीदगियों के डर से दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने में हिचकिचाते हैं। इस हिचकिचाहट के कारण "गोल्डन आवर" के कीमती मिनट बर्बाद हो जाते हैं, जब समय पर चिकित्सा देखभाल जीवन बचा सकती है।

राह-वीरों के लिए मान्यता और वित्तीय सहायता

'राह-वीर' (नेक आदमी) योजना इन व्यक्तियों को वित्तीय मान्यता भी प्रदान करती है और उन्हें वास्तविक जीवन के नायकों के रूप में सम्मानित करती है जिन्होंने संकोच के बजाय करुणा को चुना।

इस योजना के तहत, जो भी व्यक्ति दुर्घटना पीड़ित को गोल्डन आवर के भीतर चिकित्सा सहायता दिलाने में मदद करता है, उसे 25,000 रुपये का पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिया जाता है। साथ ही, बहादुरी के ऐसे कार्यों को दोहराने पर साल में पांच बार तक यह सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना आत्मविश्वास, भरोसा और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देती है जहां सड़क पर दूसरों की सहायता करना एक साझा जिम्मेदारी और राष्ट्र के लिए गर्व होता है।

राह-वीर केवल एक योजना या नीति से कहीं बढ़कर है। यह साहस, सहानुभूति और सामूहिक जिम्मेदारी है।

अगली बार जब आप कोई दुर्घटना देखें, तो याद रखेंः त्रासदी और जीवन के बीच आप ही एकमात्र उम्मीद हो सकते हैं। और किसी की जान बचाने के लिए आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, बस इंसान होना जरूरी है।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले गुवाहाटी में मानव पूंजी कार्यसमूह की बैठक आयोजित होगी

(जीएनएस)।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया एआई, असम सरकार तथा आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से 5-6 जनवरी 2026 को आईआईटी गुवाहाटी परिसर में 'मन कैपिटल वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की जाएगी। इस वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता प्रो. टी. जी. सीताराम, 'मन कैपिटल वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष एवं भारत सरकार के पूर्व एआईसीटीई अध्यक्ष, द्वारा की जाएगी। दो दिवसीय इस बैठक में वरिष्ठ नीति-निमार्ता, शिक्षाविद्, उद्योग विशेषज्ञ और प्रैक्टिशनर्स भाग लेंगे, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में शिक्षा, कौशल विकास और कार्यबल की तैयारियों के भविष्य पर विचार-विमर्श करेंगे।

इस कार्यक्रम में श्री सैयदैन अब्बासी, आईएएस, विशेष मुख्य सचिव, असम सरकार; श्री के. एस. गोपीनाथ नारायण, आईएएएस, प्रधान सचिव (आईटी), असम सरकार;

तथा श्री अश्वनी कुमार, आईएएस, निदेशक, आईटी विभाग, असम सरकार की सहभागिता रहेगी।

इस अवसर पर प्रो. जलिहाल, निदेशक, आईआईटी गुवाहाटी; प्रो. गौतम बरुआ, पूर्व निदेशक, आईआईटी गुवाहाटी; सुश्री शिखा दहिया, संयुक्त निदेशक, इंडिया एआई, टी३ सहित अन्य सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद् एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन सत्र में प्रो. टी. जी. सीताराम द्वारा एक समिट संबोधन भी दिया जाएगा, जिसमें वे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की रूपरेखा के अंतर्गत 'मन कैपिटल विजन को प्रस्तुत करेंगे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (अक) को एक सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में देखने के उद्देश्य पर आधारित यह वर्किंग ग्रुप बैठक अक-आधारित कार्यबल परिवर्तन के लिए समावेशी, स्केलेबल और जिम्मेदार दृष्टिकोणों के निर्माण पर केंद्रित होगी। विचार-विमर्श में शिक्षा सुधार, लैंगिक संवेदनशील (जेंडर-रिस्पॉन्सिव) अक रणनीतियों, तथा विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय क्षमताओं के क्षेत्र-विशिष्ट सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि अक को अपनाने की प्रक्रिया मानव क्षमता को कमजोर करने के बजाय उसे सुदृढ़ कर सके।

कार्यसूची में विशेषज्ञ पैनल चर्चाएं शामिल हैं, जिनमें अक संक्रमण के लिए लैंगिक-संवेदनशील रणनीतियाँ, संज्ञानात्मक युग के लिए शिक्षा की नई परिभाषा, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की संरचना, एक समावेशी और सशक्त भारत का निर्माण, तथा अक शिक्षा के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग दृष्टिकोण जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी।

डिजाइन आधारित प्रोत्साहन योजना, भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम को बढ़ावा

(जीएनएस)।

सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन मुख्य मूल्य चालक है, जो मूल्य वर्धन में 50 प्रतिशत तक, सामग्री सूची [बिल ऑफ मटीरियल्स (बीओएम)] की लागत में 20 50 प्रतिशत और फैबलेस सेगमेंट के जरिए वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की बिक्री में 30 35 प्रतिशत का योगदान देता है।

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की डिजाइन आधारित प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना का उद्देश्य एक आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी चिप डिजाइन इकोसिस्टम बनाना है।

24 डीएलआई-समर्थित चिप डिजाइन परियोजनाएं वीडियो सर्विलांस, ड्रोन डिटेक्शन, एनर्जी मीटरिंग, माइक्रोप्रोसेसर, सैटेलाइट कम्यूनिकेशन और आईओटी एसओसी सहित रणनीतिक क्षेत्रों को लक्षित करती हैं।

डीएलआई-समर्थित परियोजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिनमें 16 टेप-आउट, 6 एएसआईसी चिप, 10 पेटेंट, 1,000 से अधिक इंजीनियर काम कर रहे हैं और 3 गुना से अधिक निजी निवेश का सदुपयोग किया गया है।

भूमिका

भारत सेमीकंडक्टर से जुड़ी अपनी महत्वाकांक्षाओं को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। वह सेमीकंडक्टर चिप को स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, संचार, रक्षा, अंतरिक्ष और उभरते डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए अहम मानता है। तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण एवं स्वचालन की पृष्ठभूमि में, वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके जवाब में, भारत सरकार सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के जरिए, घरेलू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर रही है। चूंकि सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग कुछ ही जगहों में सीमित है, परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बेहद नाजुक और व्यवधानों की दृष्टि से संवेदनशील हो जाती हैं। यह स्थिति वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग आधार में विविधता लाने की तत्काल जरूरत को रेखांकित करती है, जिसमें भारत वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक रणनीतिक एवं भरोसेमंद भागीदार के रूप में तेजी से उभर रहा है।

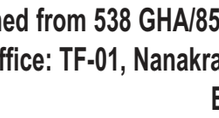

क्या आप जानते हैंः फैबलेस चिप डिजाइन सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का मुख्य आधार है

इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में, फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनियों का रणनीतिक मूल्य सबसे अधिक होता है क्योंकि वे ऐसे चिप डिजाइन करती हैं जो उत्पाद की बुद्धिमत्ता, दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाते हैं। जहां फैब्स सिलिकॉन बनाते हैं और ईएमएस फर्में उपकरण को असेंबल करती हैं, वहीं एक सेमीकंडक्टर का आधा से अधिक मूल्य वास्तविक उत्पादन से नहीं बल्कि डिजाइन और आईपी से आता है। फैबलेस सेमीकंडक्टर डिजाइन मॉडल अपेक्षाकृत कम पूंजीगत खर्च से अधिक मूल्य वर्धन सृजित करते हैं, क्योंकि डिजाइन और आईपी उत्पाद के आर्थिक मूल्य में बेहद अधिक योगदान देते हैं।

मजबूत फैबलेस क्षमता के बिना, कोई भी देश आयातित कोर तकनीक पर ही निर्भर रहता है। भले ही इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन स्थानीय पर ही क्यों न किया जाता हो। इसलिए, एक मजबूत फैबलेस इकोसिस्टम बनाने से भारत मूल्य श्रृंखला की सबसे जरूरी परत का मालिक बन सकता है, बौद्धिक संपदा को बनाए रख सकता है, आयात में कमी ला सकता है, मैन्यूफैक्चरिंग को आकर्षित कर सकता है और दीर्घकालिक तकनीकी नेतृत्व स्थापित कर सकता है।

डीएलआई योजना

डिजाइन आधारित प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना भारत की एक मजबूत फैबलेस क्षमता विकसित करने की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने का एक अहम जरिया है। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत लागू की गई है ताकि घरेलू स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वित्तीय प्रोत्साहन व डिजाइन संबंधी उन्नत बुनियादी ढांचा सुलभ कराकर एक मजबूत, आत्मनिर्भर चिप डिजाइन इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके।

डीएलआई योजना पूरी प्रक्रिया डिजाइन एवं विकास से लेकर उपयोग तक - जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी), चिपसेट, सिस्टम-ऑन-चिप (एसओसी), सिस्टम और आईपी कोर शामिल हैं - में सेमीकंडक्टर डिजाइन को समर्थन प्रदान करती है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंटेंट और बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देकर, इस योजना का उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना, आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक सुदृढ़ करना तथा घरेलू मूल्य वर्धन को बेहतर बनाना है।

डीएलआई योजना के तहत पात्रता स्टार्ट-अप और एमएसएमई

स्पर्श की अनुभूति का उत्सव : भारत में ब्रेल से संबंधित अधिकार और समावेश

(जीएनएस)।

विश्व ब्रेल दिवस

प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाने वाला 'विश्व ब्रेल दिवस' ब्रेल लिपि को केवल पढ़ने की एक प्रणाली के रूप में नहीं, बल्कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए शिक्षा, गरिमा और समान भागीदारी के प्रवेश द्वार के रूप में रेखांकित करता है। इस महत्व की झलक भारत के उन प्रयासों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहाँ समावेशी शिक्षण के लिए ब्रेल को अपनाया और मानकीकृत किया गया है। भारत में ब्रेल लिपि का आगमन 1887 में हुआ था। हालाँकि, 1951 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारती ब्रेल को एकमात्र राष्ट्रीय मानक के रूप में स्वीकार किया गया, जिसने विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए साझा कोड निर्धारित किए। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की संख्या 50,32,463 है, जिन्हें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं को समझते हुए, भारत में ब्रेल को अब एक अधिकार-आधारित इकोसिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है। यह ढांचा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 जैसी पहलों और नीतियों पर आधारित है। ये निरंतर प्रयास ब्रेल को न केवल साक्षरता के एक साधन के रूप में, बल्कि सार्वजनिक पहुँच के एक अनिवार्य मानक के रूप में स्थापित करते हैं।

ब्रेल क्या है और यह कैसे काम करती है?

ब्रेल एक स्पर्शजन्य (छू कर लिखने और पढ़ने) लेखन और पठन

प्रणाली है, जिसका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो दृष्टिबाधित हैं या जिनकी दृष्टि कमजोर है। यह छह-बिंदुओं वाले एक सेल पर आधारित होती है, जिसमें तीन-तीन बिंदुओं की दो पंक्तियाँ होती हैं। उभरे हुए इन बिंदुओं के विभिन्न संयोजन अक्षरों, संख्याओं, विराम चिह्नों और प्रतीकों को दशार्ते हैं, जिससे यूजर्स स्पर्श के माध्यम से पढ़ने में सक्षम होते हैं।

ब्रेल (जिसका नाम 19वीं सदी के फ्रांस में इसके आविष्कारक लुई ब्रेल के नाम पर रखा गया) स्वयं में कोई भाषा नहीं है, बल्कि एक कोड है जो विभिन्न भाषाओं को स्पर्शजन्य रूप (छूकर पढ़ने और लिखने) में पढ़ने और लिखने की सुविधा प्रदान करता है।

ब्रेल का महत्व

दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए साक्षरता, स्वतंत्रता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में ब्रेल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समावेशी शिक्षा और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में समान भागीदारी का मुख्य आधार है।

संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) के एक हस्ताक्षरकर्ता देश के रूप में, भारत ब्रेल सहित अन्य सुलभ प्रारूपों में सूचना और शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

भारत सरकारः ब्रेल समर्थित नीतिगत और कार्यक्रम इकोसिस्टम

भारत सरकार ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के समावेशन और सशक्तिकरण के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में, ब्रेल के विकास, प्रसार और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक इकोसिस्टम स्थापित किया है। समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय की संवैधानिक प्रतिबद्धताओं में निहित ये पहलें—शिक्षा, सामाजिक कल्याण, कौशल विकास और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्रों तक विस्तृत हैं।

1) कानूनी आधारः दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम)

भारत का ब्रेल इकोसिस्टम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के माध्यम से एक अधिकार-आधारित कानूनी ढांचे से जुड़ा हुआ है। यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा को अनिवार्य बनाता है, जिससे ब्रेल तक पहुँच और ब्रेल साक्षरता एक बुनियादी आवश्यकता बन गई है।

शैक्षणिक संस्थानों का कर्तव्य (समावेशी शिक्षा): यह अधिनियम सरकार द्वारा वित्तपोषित या मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए समावेशी शिक्षा और सुलभ बुनियादी ढांचा (भवन/कैंपस/सुविधाएं) सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाता है। इसके साथ ही, संस्थानों को छात्रों की जरूरतों के अनुसार उचित आवास और उपयुक्त सहायता प्रदान करनी होगी।

स्कूली शिक्षा में ब्रेल और संचार के माध्यमः दृष्टिबाधित (या बधिर-दृष्टिबाधित) छात्रों के लिए, यह अधिनियम संचार के सबसे उपयुक्त माध्यमों और भाषाओं में शिक्षा देने पर जोर देता है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल एसआईआर : वेद गुप्ता

- पूरा मंडल में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की समीक्षा बैठक

(जीएनएस)।

अयोध्या। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार समीक्षा बैठकों का आयोजन जारी है। इसी क्रम में पूरा ब्लॉक क्षेत्र के एक पैलेस में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और भाजपा महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव की अगुवाई में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूरा मंडल के प्रमुख महानगर पदाधिकारी और शक्ति केंद्र संयोजक शामिल हुए।

बैठक के दौरान अभियान के प्रथम चरण में किए गए कार्यों की प्रगति का बिंदुवार आकलन किया गया तथा दूसरे चरण की रणनीति पर गहन मंथन हुआ। आगामी चरण में बूथ स्तर पर गतिविधियों को और अधिक सशक्त करने पर विशेष बल दिया गया। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियों का पूरे सामर्थ्य के साथ निवार्हन करे। अभियान को सफल बनाने के लिए सम्पर्क व संवाद को और तेज करने की जरुरत है।

भाजपा महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने संगठनात्मक तालमेल के साथ लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने शक्ति केंद्र संयोजकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रत्येक शक्ति केंद्र पर स्पष्ट कार्ययोजना बनाकर दायित्व तय किए जाएं। साथ ही उन्होंने तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग व समयबद्ध फॉलोअप को अभियान की सफलता के लिए आवश्यक बताया। बैठक में महानगर महामंत्री शैलेन्द्र कोरी, हरभजन गौड़, अरविंद सिंह, कपिल देव वर्मा, दिनेश मिश्रा, देवता पटेल, प्रदीप सिंह, रमेश वर्मा, राजेश पाठक, संतोष सिंह, नीबूलाल कन्नौजिया मौजूद रहे।

राम मंदिर की सुरक्षा होगी अभेद्य, अत्याधुनिक इंतजामों के साथ बाउंड्री वॉल और वॉच टावर का निर्माण

(जीएनएस)।

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर की सुरक्षा पूरी तरह अभेद्य होगी और इसके लिए अत्याधुनिक इंतजाम किए जा रहे हैं।

नृपेंद्र मिश्रा दो दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर के चारों ओर लगभग चार किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आधुनिक सुरक्षा और निगरानी उपकरण लगाए जा रहे हैं।

उन्होंने जानकारी दी कि गेट नंबर 11, जिसे आदि शंकराचार्य द्वार के नाम से जाना जाएगा, का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस गेट पर आधुनिक सुरक्षा प्रणाली भी पूरी तरह स्थापित कर दी गई है। वहीं, जल्द ही गेट नंबर 3 के निर्माण कार्य की शुरूआत की जाएगी।

मंदिर परिसर की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए चार वॉच टावर बनाए जाएंगे। वॉच टावर और बाउंड्री वॉल के डिजाइन मॉडल को स्वीकृति मिल चुकी है और शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को गोपनीय रखा गया है।

इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए एक और सुविधा की जानकारी देते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि सप्त ऋषियों के मंदिर के दर्शन की व्यवस्था भी जल्द प्रारंभ की जाएगी, जिससे भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव का और विस्तार मिलेगा।

थाना कोतवाली रुदौली पुलिस टीम ने विधुत तार चोरी घटना का सफल अनावरण कर 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

चोरी का सामान कीमत लगभग 5 लाख बरामद।

(जीएनएस)।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद अयोध्या डा0 गौरव ग्रोवर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रूदौली द्वारा विधुत तार चोरी गैंग का अनावरण करने हेतु पुलिस टीमों का गठन कर अनावरण में लगाया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियान त्रिनेत्र के अन्तर्गत थाना क्षेत्र में स्थापित कैमरो की मदद 48 घण्टे के अन्दर घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 अभियुक्तों को मय माल के गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है। उक्त घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर 02/2026 धारा 303(2) ,317(2) / 3(5) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत है ।

अभियुक्त का नाम पताः

1.मनीष पाण्डेय पुत्र राजाराम पाण्डेय निवासी ग्राम परडी शाहगंज थाना इनायतनगर अयोध्या

अपराधिक इतिहास– मु0अ0सं0 308/24 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना तारुन अयोध्या

2. कृष्ण कुमार पुत्र अमरनाथ नि0 कनकपुर सगरौली थाना तारून अयोध्या

3. गंगादीन पुत्र अंगद प्रसाद नि0 बन्नी पीपरी थाना बीकापुर अयोध्या

4. मनोज यादव पुत्र रामभवन यादव नि0 ग्राम शंकरपुर विक्रमजोत थाना छावनी जनपद बस्ती

5. आशीष साहू पुत्र अमर प्रसाद नि0 ग्राम पुरे जोधी शुक्ल का पुरवा थाना इनायत नगर अयोध्या

बरामदगी का विवरण –

1. 13 बंडल एल्युमीनियम का तार 33 केवी
2. तीन फेस केबिल 01 बंडल
3. एलटी एबीसी केबिल 04 बंडल
4. एलटी एबीसी केबिल
5. 395 एक बंडल
6. बीजल कंडक्टर 01 बंडल
7. एमएस चैनल एंगल 21 पीस
8. क्रास एआरएम 18 पीस
9. होल्डिग क्लेम्प 31 पीस
10. 01 अदद लोहे का कटर
11. 02 अदद लोहे की आरी, ,
12. 01 अदद लोहे का पेचकस
13. 02 अदद रिंच
14. 05 अदद मोबाईल टच स्क्रिन घटना में प्रयुक्त
15. 01 अदद घटना में प्रयुक्त पीकप वढ 32 फ्ठ 8540

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. संजय मौर्य प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रूदौली अयोध्या
2. निरीक्षक शत्रुघन यादव
3. उ0नि0विपिन श्रीवास्तव
4. उ0नि0 अभय प्रताप सिंह
5. उ0नि0 अभिषेक सिंह
6. उ0नि0 गजेन्द्र कुमार
7. हे0का0 राजेश यादव
8. का0 रजत कुमार

रामनगर में चौकीदार के घर आग, तीन पशु झुलसे:शॉर्ट सर्किट से लाखों का सामान राख, 3 लाख का नुकसान

बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई।

बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई।

बाराबंकी जिले की रामनगर तहसील के ग्राम पंचायत हथोइया के मजरा धौरछिया में शनिवार रात करीब 3:30 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में रामनगर थाने में चौकीदार के पद पर तैनात रामशंकर पुत्र तुलसीराम का छप्परनुमा घर जल गया। आग की चपेट में आने से घर में बंधी एक भैंस और उसके दो बच्चे झुलस गए।

आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक घर का अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था। पीड़ित रामशंकर और रामवीर ने बताया कि राशन, चारपाई, संदूक, साइकिल, पंपिंग सेट और भूसे में रखी गेहूं की चार बोरियां सहित गृहस्थी का पूरा सामान नष्ट हो गया।

इस अग्निकांड में करीब तीन लाख रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। घटना के बाद पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है।

घटना के बाद बिजली विभाग के स्थानीय कर्मचारियों को कई बार फोन पर सूचना दी गई, लेकिन घंटों तक उनका फोन नहीं उठा। करीब पांच घंटे बाद बिजली की आपूर्ति बंद की जा सकी।

ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। रामनगर की उप जिलाधिकारी गुंजिता अग्रवाल ने बताया कि मामले की जांच के लिए तत्काल लेखपाल को मौके पर भेजा गया है और पीड़ित परिवार को राहत दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। पशु चिकित्साधिकारी बसंत राय पाटिल ने भी मौके पर चिकित्सक भेजकर झुलसे हुए पशुओं का इलाज शुरू कराया।

वहीं, बिजली विभाग के एसडीओ ने बताया कि विद्युत केंद्र सूरतगंज से कर्मचारियों को मौके पर भेजा जा रहा है और मामले की जांच की जाएगी।

दलित परिवार की जमीन पर जबरन कब्जे का प्रयास, खड़ी फसल रौंदी, विरोध पर लाठी-डंडों से पीटा, पुलिस पर एफआईआर न दर्ज करने का आरोप

बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में दलित परिवार की जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने, गेहूं की खड़ी फसल नष्ट करने और जातिसूचक गालियों के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार पुलिस पर विपक्षियों से साठगांठ कर एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगा रहा है। पढ़ें पूरी खबर विस्तार से

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

बाराबंकी जिले के लोनी कटरा थाना क्षेत्र से दबंगई और कठित भू-माफिया के आतंक का एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने जिले की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंगों द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने, फसल नष्ट करने और मारपीट की घटना को चार दिन बीत जाने के बावजूद स्थानीय पुलिस विपक्षियों से साठगांठ के चलते अब तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है।

हसवापुर मजरे खैरा कनकू गांव का मामला

ग्राम हसवापुर मजरे खैरा कनकू निवासी अनुसूचित जाति के गरीब खेतिहर मजदूर बाबूलाल पासी पुत्र जगेसर पासी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दिनांक 30 दिसंबर 2025 की शाम करीब 5 बजे वह अपने परिवार के साथ अपनी गाटा संख्या–1006 मिन में लगी गेहूं की फसल की सिंचाई कर रहा था।

इसी दौरान अयोध्या प्रसाद पुत्र बैजू निवासी नई बस्ती अर्जुनगंज, जनपद लखनऊ अपनी पत्नी, माता, भाई समेत करीब 50 अज्ञात लोगों के साथ मौके पर पहुंचा। इनके लगभग 30 महिलाएं और 20 पुरुष शामिल थे, जो चार चारपहिया वाहनों और करीब 10 मोटरसाइकिलों से आए थे।

यह भी पढ़ें इं१ुल्ल्ः बाग में पेड़ पर लटका मिला शुक्रवार की सुबह घर से निकले अधेड़ का शव, परिजनों ने दोस्तो पर लगाया हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

लात-घूंसो व लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट

पीड़ित का आरोप है कि विपक्षियों ने बिना किसी वैधानिक आदेश के जबरन उसकी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से दो ट्रैक्टरों से खेत की जुताई कर गेहूं की खड़ी फसल को नष्ट करना शुरू कर दिया। जब बाबूलाल और उसके परिजनो ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मां बहन की भद्दी-भद्दी गालियां दी और लात-घूंसो व लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी।

मारपीट में महिलाओं बच्चों समेत कई घायल

पीड़ित के अनुसार अयोध्या प्रसाद ने जान से मारने की नीयत से उसका गला दबाया और जमीन पर पटक दिया। आरोप है कि विपक्षियों के साथ मौजूद एक वकील ने बाबूलाल की पत्नी कल्पवती को भी लात मारकर गिरा दिया। शोर-शराबा सुनकर गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह पीड़ित परिवार को बचाया।

जाते-जाते आरोपी धमकी देकर गए कि आज तो बच गए, अगली बार जान से मार देंगें। मारपीट में बाबूलाल, उसकी पत्नी कल्पवती, पुत्र रामसिंह, बहू सरिता समेत परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

यह भी पढ़ें इं१ुल्ल्ः अभिनव श्रीवास्तव बने उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष, अजीत प्रताप सिंह को 17 मतों से चटाई धूल

नहीं उठा थानाध्यक्ष का सीयूजी नंबर

पीड़ित की पुत्री एडवोकेट अनुष्का, जो बाराबंकी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, ने बताया कि घटना के दौरान उन्होंने 4-5 बार थानाध्यक्ष लोनी कटरा के सीयूजी नंबर पर फोन किया, लेकिन विपक्षियों से कथित साठगांठ के चलते फोन नहीं उठाया गया। इसके बाद उन्होंने डायल-112 पर सूचना दी, साथ ही पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी बाराबंकी और एसडीएम हैदरगढ़ को फोन कर मदद मांगी। काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर परिवार की जान बच सकी।

देखें घटना का वीडियो

घंटों थाने में बैठाने के बाद भी कार्रवाई शून्य

पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना वाले दिन ही वे लोनी कटरा थाने पहुंचे और लिखित तहरीर दी, लेकिन न तो उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई और न ही घायलों का मेडिकल कराया गया। घंटों थाने में बैठाने के बाद उन्हें अगले दिन आने की बात कहकर वापस कर दिया गया। अगले दिन थाने पहुंचने पर थानाध्यक्ष ने इसे राजस्व विवाद बताकर एसडीएम हैदरगढ़ से संपर्क करने की सलाह दे दी।

एसडीएम और बीजेपी विधायक के निर्देश भी बेअसर

पीड़ित का कहना है कि इसके बाद उन्होंने एसडीएम हैदरगढ़ और क्षेत्रीय विधायक दिनेश रावत से भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उनके निर्देशों के बाद भी थानाध्यक्ष लोनी कटरा अब तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। वही दूसरी ओर आरोपी लगातार पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकीं दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि विपक्षी भू-माफिया प्रवृत्ति के दबंग लोग है, जिनसे उन्हें जान-माल का गंभीर खतरा बना हुआ है।

सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन

सीतापुर – जनता की शिकायतों एवं समस्याओं को स्थानीय स्तर पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 05 जनवरी 2026 दिन सोमवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन प्रत्येक तहसील में किया जाएगा। उक्त तिथि को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील सिधौली में सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजन प्रस्तावित है।

गहनाग बाबा स्थल का होगा कायाकल्प, एक करोड़ रुपये से विकसित होंगी पर्यटन सुविधाएं

(जीएनएस)।

मिल्कीपुर विधायक के प्रस्ताव को तीर्थ विकास परिषद से मिली मंजूरी

अयोध्या। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित इनायतनगर गहनाग बाबा स्थल पर शीघ्र ही पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मिल्कीपुर विधायक चन्द्रभानु पासवान द्वारा अयोध्या तीर्थ विकास परिषद को भेजे गए प्रस्ताव पर निदेशालय ने एक करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी है। स्वीकृत राशि से स्थल पर बुनियादी एवं पर्यटक सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा।

न गहनाग बाबा स्थल क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहां विभिन्न धार्मिक अवसरों पर मेले और कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिनमें दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं। यहां आधारभूत और पर्यटन सुविधाओं के विकास की आवश्यकता सामने आती रही हैं। स्थानीय लोगों द्वारा लगातार इस स्थल के विकास की मांग उठाई जाती थी।

स्थानीय जनता की भावनाओं और मांग को ध्यान में रखते हुए मिल्कीपुर विधायक चन्द्रभानु पासवान ने आस्तीकन गहनाग बाबा स्थल के पर्यटन विकास का प्रस्ताव तैयार कर अयोध्या तीर्थ विकास परिषद को भेजा था। इसके बाद इस परियोजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रेषित परियोजनाओं की सूची में सम्मिलित कर लिया गया। इस संबंध में अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा विधायक को पत्र लिखकर यह जानकारी दी गई कि आस्तीकन गहनाग बाबा स्थल पर पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए एक करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

स्वीकृति मिलने के बाद विधायक चन्द्रभानु पासवान ने कहा कि आस्तीकन गहनाग बाबा स्थल न केवल क्षेत्र की आस्था का प्रतीक है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां पर्यटन सुविधाओं के विकास से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश भर में धार्मिक और पर्यटन स्थलों के समग्र विकास का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उसी क्रम में मिल्कीपुर विधानसभा के इस महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल को भी विकसित किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि कार्य को शीघ्र प्रारंभ कर गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूरा कराया जाएगा, ताकि आस्तीकन गहनाग बाबा स्थल श्रद्धा के साथ-साथ पर्यटन के मानचित्र पर भी एक नई पहचान बना सके।

अयोध्या के दो राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुरू हुई नई डिजिटल सुविधाएं

(जीएनएस)।

अयोध्या। अयोध्या से गुजरने वाले दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच-27 (रामसनेही घाट से गोरखपुर) और एनएच-330ए (जगदीशपुर से अयोध्या) पर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा नई डिजिटल व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इन पहलों का उद्देश्य यात्रियों को आवश्यक जानकारी, सुरक्षित यात्रा और डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रमुख स्थानों पर क्यूआर कोड युक्त साइनबोर्ड लगाए गए हैं। ये बोर्ड टोल प्लाजा, विश्राम स्थल, ट्रक पार्किंग, वेजसाइड एमेनिटी तथा हाईवे के प्रारंभ और समाप्ति बिंदुओं पर स्थापित किए गए हैं। क्यूआर कोड स्कैन करने पर यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्ग का नंबर, चेनेज, परियोजना की लंबाई, निर्माण व रखरखाव अवधि, संबंधित अधिकारियों के संपर्क नंबर, आपातकालीन हेल्पलाइन 1033 और आसपास उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मिल सकेगी।

टोल प्लाजा पर भुगतान व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए डायनेमिक क्यूआर कोड सिस्टम लागू किया गया है। जिन वाहनों के पास फास्टैग नहीं है, वे टोल बूथ पर लगे 18 इंच के टीएफटी/एलईडी मॉनिटर पर प्रदर्शित क्यूआर कोड को स्कैन कर यूपीआई के माध्यम से टोल शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। यूपीआई से भुगतान करने पर सामान्य फास्टैग शुल्क की तुलना में 1.25 गुना शुल्क देना होगा। इसके साथ ही एनएच-27 और एनएच-330ए पर विशेष रोड मार्किंग भी कराई गई है। इन मार्किंग्स के माध्यम से लेन अनुशासन, गति सीमा, ओवरटेकिंग नियम और अन्य यातायात संकेत स्पष्ट किए गए हैं, जिससे वाहन चालकों को मार्ग पर आवश्यक दिशा-निर्देश मिल सकें। एनएचएआई, पीआईयू अयोध्या के परियोजना निदेशक अवनीत सिद्धार्थ के अनुसार, इन व्यवस्थाओं से अयोध्या आने-जाने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान आवश्यक जानकारी और भुगतान में सुविधा मिलेगी।

बाराबंकी में भू-माफिया ने किसान की फसल नष्ट की:खेत पर कब्जे का प्रयास, लखनऊ से आए लोगों ने परिवार को पीटा

बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील में भू-माफियाओं ने एक बुजुर्ग किसान की गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से जोतकर नष्ट करने का प्रयास किया। आरोप है कि भू-माफियाओं ने किसान और उसके परिवार के साथ मारपीट भी की। पीड़ित किसान ने उपजिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।

यह घटना 30 दिसंबर 2025 को शाम करीब 5 बजे थाना लोनीकटरा के ग्राम हसवापुर मजरे खैराकनकू में हुई। पीड़ित बाबूलाल पुत्र जगेसर अपनी गाटा संख्या 1006मि० में लगी गेहूं की फसल की सिंचाई करने परिवार सहित खेत पर गए थे।

उसी दौरान अयोध्या प्रसाद पुत्र बैजू निवासी नई बस्ती अर्जुनगंज, लखनऊ, अपनी पत्नी, माता, वकील और लगभग 50 अज्ञात व्यक्तियों (30 महिलाएं, 20 पुरुष) के साथ चार गाड़ियों और 10 मोटरसाइकिलों से मौके पर पहुंचे। आरोप है कि इन लोगों ने बिना किसी आदेश के दो ट्रैक्टरों से बाबूलाल की फसल को जोतना शुरू कर दिया।

जब बाबूलाल और उनके परिवार ने इसका विरोध किया, तो भू-माफिया अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद विपक्षीजनों ने बाबूलाल के परिवार को गालियां दीं और लात-घूसों व डंडों से मारपीट करने लगे। अयोध्या प्रसाद ने बाबूलाल का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की और उन्हें जमीन पर गिरा दिया।

गांव के कुछ लोगों ने बीच-बचाव कर बाबूलाल को बचाया। इस मारपीट में बाबूलाल और उनके परिवार के सदस्यों को चोटें आई हैं। जाते समय भू-माफियाओं ने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने तत्काल 112 नंबर और स्थानीय थाने को सूचना दी।

उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को मौके पर भेजा, जिसने बाबूलाल और उनके परिवार को भू-माफियाओं से बचाया। इस संबंध में उपजिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अवैध कब्जा करने की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्यवाही के लिए थाने को निर्देश दिए गए हैं।

आजमगढ़: आजमगढ़ में जमीन पर गुंडाराज, दबंग बेखौफ, पीड़ित को मिली धमकी का इनाम, कानून व्यवस्था बनी तमाशबीन

जब पैमाइश कागजात और सच सब सामने है फिर भी दबंग का मनोबल किसके दम पर आसमान छू रहा है बड़ा सवाल आजमगढ़ की जनता पूछ रही है क्या कानून सिर्फ फाइलों में जिंदा है और जमीन पर अभी दबंग का राज कायम है रानी की सराय थाना क्षेत्र के कयामपुर स्थित खाली जमीन पर राम सिंगर उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय उदराज उपाध्याय से विधवाहट एग्रीमेंट कराया था पड़ोसियों का कब्जा डंडों केबल पर

ग्राम चौपालों से गांव में ही हो रहा समस्याओं का समाधान, 6 लाख से अधिक प्रकरण निस्तारित : केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ। प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम चौपालों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान गांव में ही सुनिश्चित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व एवं निर्देशन में प्रत्येक विकास खंड की दो ग्राम पंचायतों में प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल, गांव की समस्या गांव में समाधान, का आयोजन किया जा रहा है। इन चौपालों के जरिए ग्रामीणों की व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है।

डबल इंजन सरकार की इस पहल से प्रशासन स्वयं गांव और गरीबों के पास पहुंच रहा है। ग्राम चौपालों के माध्यम से जहां गांवों में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की जमीनी हकीकत सामने आ रही है, वहीं सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आई है। उप मुख्यमंत्री के निदेशों के अनुपालन में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ठोस और प्रभावी रूपरेखा तैयार कर चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। चौपाल से पूर्व गांवों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अधिक से अधिक ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।

ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश की 1326 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपालों का आयोजन किया गया। इन चौपालों में कुल 3295 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। आयोजन के दौरान 3295 ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी तथा 5599 ग्राम स्तरीय कर्मचारी उपस्थित रहे। ग्राम चौपालों में 64 हजार से अधिक ग्रामीणों ने सहभागिता की।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश में 1 लाख 80 हजार से अधिक ग्राम चौपालों का आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से 6 लाख से अधिक समस्याओं एवं प्रकरणों का समाधान गांव स्तर पर ही किया गया है।

काशी में 28 से अधिक रैनबसेरे बने बेसहारा लोगों का सहारा

काशी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार देर रात टाउनहॉल रैनबसेरे का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि काशी के भीतर बनाए गए 28 से अधिक रैनबसेरे हजारों जरूरतमंदों, बेसहारा और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए सहारा बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि भीषण शीतलहरी के मद्देनजर प्रत्येक जनपद को ऊनी वस्त्र वितरण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है और प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जरूरतमंदों को युद्ध स्तर पर कंबल और गर्म कपड़े वितरित किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उनकी संसदीय सीट काशी के लिए पिछले 11 वर्षों में 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से दो तिहाई से अधिक परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि शेष पर कार्य तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि काशी में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है।

सीएम योगी ने कहा कि भीषण ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा रैनबसेरों के साथ-साथ अस्थायी ठहराव की भी व्यवस्था की गई है। टाउनहॉल में बनाए गए अस्थायी रैनबसेरे में देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु ठहरे हुए हैं, जिनकी सुविधाओं का निरीक्षण भी किया गया। उन्होंने कहा कि काशी आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नगर निगम स्तर पर स्थायी रैनबसेरों के माध्यम से गरीबों और निराश्रितों को सुरक्षित आश्रय दिया जा रहा है। कंबल वितरण कार्यक्रम में स्वयं शामिल होकर उन्होंने जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की और कहा कि सरकार ठंड के इस दौर में हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है।

खेल शक्ति ही राष्ट्र शक्ति : 'नई खेल संस्कृति के साथ यूपी बना रहा राष्ट्रीय नेतृत्व': मुख्यमंत्री योगी

72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के शुभारंभ पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

खेलो इंडिया, फिट इंडिया और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ने बदली खेलों की तस्वीर, गांव से ग्लोबल मंच तक दिख रहा परिणाम

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यूपी खेल निदेशालय के बीच एनसीओई संचालन के लिए एमओयू, युवा खिलाड़ियों को मिलेगा अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म

हर जिले में खेल सुविधाओं का विस्तार, ओलंपिक-कॉमनवेल्थ जैसे बड़े मंचों पर यूपी के खिलाड़ियों की बढ़ती उपलब्धियाँ

वाराणसी, 4 जनवरीः

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश और देश में खेल को नई दृष्टि, नए संसाधन और नया आत्मविश्वास मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उभरते ह्न्यू स्पोर्ट्स कल्चरह्व ने युवाओं में अनुशासन, फिटनेस और टीम-स्पिरिट को मजबूत किया है। अब खेल सिर्फ शौक नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, पारदर्शी चयन-प्रक्रिया और मिशन-मोड पर चल रही योजनाओं के चलते युवा खिलाड़ियों के लिए अवसर बढ़े हैं। ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रतियोगिताओं का विस्तार किया गया है। परिणामस्वरूप यूपी के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पहले से कई गुना अधिक भागीदारी और पदक ला रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 72वीं सीनियर नेशनल वालीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअली शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आयोजन स्थल डॉ. संपूणानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिगरा में मौजूद रहे। उन्होंने यहां खिलाड़ियों व दर्शकों को संबोधित किया। सीएम की उपस्थिति में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया व उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के मध्य नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एनसीओई) के संचालन के लिए एमओयू का आदान-प्रदान हुआ। सीएम योगी ने काशी में आई सभी 58 टीमों (30 पुरुष, 28 महिला) के खिलाड़ियों, कोच व ऑफिशियल का स्वागत किया।

हर भारतवासी ने देश में नई खेल संस्कृति को पनपते देखा

सीएम योगी ने कहा कि पिछले 11- साढ़े 11 वर्ष के अंदर हर भारतवासी ने देश में नई खेल संस्कृति को पनपते देखा है। पीएम मोदी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से हर भारतवासी के मन में खेल के प्रति सम्मान का भाव पैदा किया। उन्होंने संदेश दिया कि खेल जीवन के सर्वांगीण विकास का माध्यम बने। स्वस्थ शरीर से ही सफलता के सभी आयाम प्राप्त किए जा सकते हैं। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता और हर जनपद में बनने वाले खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पूरा देश नई खेल संस्कृति का अनुभव कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सांसद-विधायक खेलकूद प्रतियोगिता, ग्रामीण खेलकूद की विभिन्न प्रतियोगिता आदि के माध्यम से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण, अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों की हौसलाअफजाई भी की

मुख्यमंत्री ने स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण भी किया। यहां जिम और इसके उपकरणों के रखरखाव को देखा। सीएम ने शूटिंग के एक बच्चे को बुलाकर उससे खेल के बारे में पूछा, इस बच्चे ने सीएम के सामने निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न खेलों में अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की।

प्रदेश व देश में विकसित हुआ खेल का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर

सीएम ने कहा कि 43 वर्ष बाद सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन यूपी के अंदर वाराणसी नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन के पीछे पीएम मोदी की प्रेरणा, मार्गदर्शन व नेतृत्व है। उन्होंने कहा कि प्रदेश-देश में खेल का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है। संपूणानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है तो यह पीएम मोदी के विजन का परिणाम है। यह सुविधाएं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकसित हुई हैं। अभी उप्र सरकार व साईं के बीच हुए एमओयू के अंतर्गत साई के सानिध्य और कोच के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा।

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग के साथ ही अधिक से अधिक मेडल प्राप्त कर रहे खिलाड़ी

सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 8-साढ़े 8 वर्ष में खेलकूद प्रतियोगिता को बढ़ाने का कार्य हुआ। हर गांव में खेल मैदान, हर जनपद में स्टेडियम, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण, नगर निकाय व ग्राम पंचायत से होने वाले कार्यों की प्राथमिकता में ओपन जिम निर्माण के साथ ही हर स्तर पर खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ाने के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। उसी का परिणाम है कि हमारा खिलाड़ी राष्ट्रीय, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ व इंटरनेशनल विश्व चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के साथ ही पहले की तुलना में कई गुना मेडल भी प्राप्त कर रहा है।

महापौर अशोक तिवारी ने अतिथियों का स्वागत किया। शुभारंभ समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र 'दयालु', खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विधायक नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, डॉ. सुनील पटेल, त्रिभुवन राम, डॉ. अवधेश सिंह, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

ट्रेनर दीदी बनीं लखपति, सेफ मोबिलिटी से गोरखपुर की महिलाओं को मिली आत्मनिर्भरता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण अब योजनाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जमीन पर इसकी तस्वीर साफ नजर आने लगी है। गोरखपुर की मंशा देवी इसकी जीवंत मिसाल हैं, जिन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति बदली, बल्कि 60 से अधिक महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया है। एक वर्ष के भीतर लखपति दीदी बनी मंशा देवी अब 26 जनवरी को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी।

कभी सीमित संसाधनों में परिवार चलाने वाली मंशा देवी ने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर समूह सखी के रूप में काम शुरू किया। सेफ मोबिलिटी कार्यक्रम से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी ने नई दिशा पकड़ी। आज वे ई-रिक्शा ट्रेनर के रूप में दिन-रात बेखौफ सड़कों पर फरार्टा भर रही हैं और अन्य महिलाओं को ड्राइविंग, लाइसेंस और उद्यमिता का प्रशिक्षण दे रही हैं। उनकी मासिक आय 20 से 30 हजार रुपये तक पहुंच चुकी है, जिससे सालाना आय ढाई से तीन लाख रुपये के करीब हो गई है। सेफ मोबिलिटी कार्यक्रम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मिशन निदेशक दीपा रंजन के निर्देशन में डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स एवं आजीविका मिशन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। सुरक्षित परिवहन के माहौल और सरकारी योजनाओं से मिले वित्तीय सहयोग ने महिलाओं के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है।

मंशा देवी ने ब्रह्मपुर ब्लॉक के साथ-साथ जिले के अन्य ब्लॉकों की महिलाओं को भी प्रशिक्षण देना शुरू किया। मुद्रा योजना से 1.25 लाख रुपये और ब्लॉक स्तर से एक लाख रुपये की सहायता मिलने के बाद उनके कार्य ने रफ्तार पकड़ी। आज उनके समूह से जुड़ी महिलाएं सुरक्षित माहौल में ई-रिक्शा चलाकर नियमित आय अर्जित कर रही हैं। मंशा देवी की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि सही नीति, प्रशिक्षण और अवसर मिलें तो ग्रामीण महिलाएं न केवल खुद आत्मनिर्भर बनती हैं, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाने की ताकत भी रखती हैं।

लाखों की भीड़ में छह माह से लापता बेटे को खोजने माघ मेले में पहुंचे मां-बाप

प्रयागराज। संगम की रेती पर फैले माघ मेले की भीड़ में उस दिन आस्था के साथदृसाथ एक असहनीय पीड़ा भी बह रही थी। आगरा से आए एक दंपती के हाथ में बेटे की तस्वीर थी। उसी तस्वीर को सीने से लगाए वे हर चेहरे में अपने लाल को खोज रहे थे।

संगम की रेती पर फैले माघ मेले की भीड़ में उस दिन आस्था के साथदृसाथ एक असहनीय पीड़ा भी बह रही थी। आगरा से आए एक दंपती के हाथ में बेटे की तस्वीर थी। उसी तस्वीर को सीने से लगाए वे हर चेहरे में अपने लाल को खोज रहे थे। कोई अनजान मिलता तो आंखों में उतर आई उम्मीद के साथ वे पूछ बैठते, भइया, क्या आपने इस लड़के को कहीं देखा है। भीड़ के शोर में उनकी आवाज कई बार दब जाती, पर सवाल हर बार वही रहता।प्रयागराज पर्यटन जानकारी

आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के रामबाग से आए राजीव कुशवाहा और उनकी पत्नी पूनम अपने बेटे शिव कुशवाहा की फोटो लेकर पूरे माघ मेले में घूम रहे हैं। संगम नोज से लेकर अक्षय वट, हनुमान मंदिर, राम घाट लेकर महावीर रोड और संगम के सभी घाटों पर जा रहे हैं। वह लोगों को फोटो दिखाकर पूछ रहे हैं कि इस लड़के को कहीं देखा है। दंपती के मुताबिक उनका इकलौता बेटा शिव कुशवाहा 24 जून 2025 से लापता हो गया है।

बताया कि जहां भी उम्मीद की एक किरण दिखी, वहां पहुंचे। पोस्टर छपवाए, फोन किए, अनजान नंबरों पर भरोसा किया, पर हर कोशिश निराशा में बदलती चली गई। वक्त के साथ आंखों की नमी सूखने लगी, पर इंतजार खत्म नहीं हुआ। माघ मेले की खबर सुनकर उनके भीतर एक नई आस जागी। लाखों श्रद्धालु आते हैं, कहीं न कहीं किसी की नजर पड़ ही जाएगी। यही सोचकर वे संगम तट पर पहुंच गए। संगम की ओर बढ़ती भीड़ के बीच वे रुक-रुक कर तस्वीर दिखाते, लोगों से पूछते, और हर नहीं पर मन को समझाते। अगले मोड़ पर शायद हां मिल जाए।

दंपती की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। मां की हथेलियां कांपतीं तो पिता चुपचाप बेटे की तस्वीर को सीधा करते मानो वह कहीं से देख रहा हो और तस्वीर टेढ़ी न लगे। वे कहते हैं, आंखें पथरा गई हैं, पर उम्मीद जिंदा है। जब तक सांस है, तलाश जारी रहेगी। उनके लिए जीवन का एकमात्र उद्देश्य अब वही है। बेटे को खोज निकालना।

मेले की चहल-पहल के बीच उनकी कहानी कई दिलों को छू गई। कुछ लोगों ने तस्वीर अपने फोन में ली, कुछ ने सोशल मीडिया पर साझा करने का भरोसा दिया, किसी ने पुलिस हेल्पडेस्क का रास्ता दिखाया। हर छोटी मदद उनके लिए बड़ा सहारा बनती गई। शाम ढलतेदृढलते थकान चेहरे पर थी, मगर कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मां पूनम ने बताया कि उन्होंने गंगा मैया से बेटे के लिए मनौती मांगी है। बेटा मिल जाएगा तो उसके साथ वह फिर मां गंगा में स्नान करने के लिए आएंगे।

प्रयागराज में आईएएस के मकान में चल रहा सेक्स रैकेट

प्रयागराज। प्रयागराज में आईएएस के मकान में सेक्स रैकेट चल रहा था। रविवार को पुलिस रेड में 4 लड़कियां और 5 लड़के आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। पुलिस ने सभी को हिरासत में थाने लेकर गई है। कहा जा रहा है कि यह मकान 3 महीने पहले 15 हजार रुपए महीने के किराए पर लिया गया था।

मौके से कुछ आपत्तिजनक सामग्री और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह रैकेट कब से चल रहा था। इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। छापेमारी की कार्रवाई नई बस्ती कीडगंज में हुई।

दरवाजा नहीं खोला, तो पुलिसवालों ने तोड़ दियासुरक्षा उपकरण बिक्री

कीडगंज की नई बस्ती में आईएएस वंदना त्रिपाठी दो मंजिला मकान है। पिछले कई महीनों से इस मकान में लड़के-लड़कियों का आना-जाना लगा रहता था। रात में भी कई लोग आते-जाते थे। इस पर आसपास रहने वाले लोगों को शक हुआ। उन्होंने रविवार को कीडगंज थाना पुलिस को सूचना दे दी।

२५ ल्ली६२

पता चलते ही रविवार दोपहर करीब 2 बजे थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह और एसीपी राजीव यादव ने मकान पर छापा मारा। घर में ताप्य पड़ने का पता चलते ही अंदर मौजूद लड़के-लड़कियों ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद पुलिसवालों ने दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस जब अंदर पहुंची, तो अलग-अलग कमरों में लड़के-लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मौजूद थे।

पुलिस को देखकर सभी आसपास खुद चादर या दूसरे कपड़ों से ढंकने लगे। पुलिस को कमरे के अंदर आपत्तिजनक सामान भी मिला। पुलिस ने 2 कमरों से 4 लड़कियों और 4 लड़कों को हिरासत में ले लिया। वहीं, बाहर बैठकर पहरेदारी कर रहे सरगना को भी पुलिस ने पकड़ लिया।

3 महीने पहले 15 हजार रुपए के किराए पर लिया मकान

सरगना का नाम सर्वेश द्विवेदी है। वह प्रयागराज में दरियाबाग के अतरसुइया का रहने वाला है। सर्वेश ने पुलिस को बताया- मैंने आईईआरएस अमिताभ शर्मा और आईएएस वंदना त्रिपाठी से 3 महीने पहले 15 हजार रुपए महीने किराए पर मकान लिया था। इसका मैंने एग्रीमेंट भी कराया था कि फैमिली के साथ रहूंगा।प्रयागराज पर्यटन जानकारी

वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्वेश 10-15 दिन के लिए अपने परिवार को इस घर में लेकर आया था। इसके बाद यहां संदिग्ध गतिविधियां शुरू हो गईं। इससे मोहल्लेवालों को भी परेशानी हो रही थी। बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा था।

एक लड़की पश्चिम बंगाल की, तो दूसरी वाराणसी की

छापेमारी के दौरान पकड़ी गई 4 लड़कियों में से एक पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। दूसरी लड़की वाराणसी की रहने वाली है। वहीं अन्य 2 लड़कियां प्रयागराज की हैं। पश्चिम बंगाल की लड़की ने बताया कि मैं फेसबुक से इनके संपर्क में आई थी। इसके बाद मैं यहां आ गई।

बाराबंकी में गाय ने अलाव से ली गर्मी:पुलिस चौकी पर दिखा मानवीय चेहरा, ठंड से राहत

लोधेश्वर महादेव धाम की पुलिस चौकी पर एक गाय अलाव की गर्मी सेंकती नजर आई।

बाराबंकी जिले में कड़ाके की ठंड के बीच एक मानवीय दृश्य देखने को मिला। रामनगर तहसील स्थित लोधेश्वर महादेव धाम की पुलिस चौकी पर एक गाय अलाव की गर्मी सेंकती नजर आई। पुलिसकर्मियों ने ठंड से परेशान गाय को नहीं भगाया, जिससे यह घटना चर्चा का विषय बन गई।

जनपद बाराबंकी की रामनगर तहसील इन दिनों भीषण शीतलहर की चपेट में है। कड़ाके की ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, और सुबह-शाम सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। ठंड से बचाव के लिए जगह-जगह अलाव जलाए जा रहे हैं।

इस बार उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप इतना अधिक है कि तापमान के मामले में कई शहरों ने शिमला को भी पीछे छोड़ दिया है। यह ठंड केवल इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पशु-पक्षियों और अन्य जीव-जंतुओं पर भी इसका गहरा असर देखा जा रहा है। जहां लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं, वहीं बेजुबान जानवर भी गर्मी की तलाश में भटक रहे हैं।

ऐसा ही एक हृदयस्पर्शी दृश्य रविवार शाम करीब 5 बजे लोधेश्वर महादेव धाम स्थित महादेव चौकी पर सामने आया। पुलिस प्रशासन द्वारा यहां ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। कड़ाके की ठंड से परेशान एक घुमंतू गाय अलाव की गर्मी लेने के लिए चौकी पर आ गई। अलाव के पास खड़े होकर गाय काफी देर तक वहीं रही और गर्मी सेंकती रही।

चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि ठंड से परेशान गाय को देखकर किसी ने उसे वहां से नहीं भगाया। उन्होंने कहा कि गाय को माता का स्वरूप माना जाता है और जब भी अलाव जलता है, यह गाय अक्सर वहां आकर गर्मी लेती है। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जैसे इंसानों को ठंड लगती है, वैसे ही जानवरों को भी ठंड महसूस होती है।